(c) The practice of spot purchase is restored to only in a few exceptional cases of emergency, but no sub-standard or defective spares are accepted.

(d) and (e) No, Sir.National Railway Mazdoor Union, Pune had in its representation pointed out certain difficalties in maintenance of DC locomotives including failures being caused by shortage and poor quality of materials. This was investigated and discussed in detail with the Union in the PNM Meeting and the above position aprised. No specific action was called for.

Computerised Ticketing and Enquiries by Private Parties

1447. SHRI K. R. MALKANI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the Hon'ble Minister of Railways and the Chairman Railway Board had said on Zee T.V. programme 'Help Line' last month that necessary action on computerised ticketing and enquiries through private agencies will be taken shortly,

(b) if so, how long the same is likely *to* take;and

(c) whether Government would announce a time frame for this widespread demand, pending for years?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): (a) to (c) The issue raised in the Zee -TV programme related to the increase in the number of reservation, offices for the convenience of the travelling public. It is the policy of the "Indian Railways to provide the facility of passenger reservations at a larger number, of outlets particularly in the important" cities. As part of this effort, modalities for providing this facility at more locations, including City Booking Offices in such cities, are under consideration.

अधिशेष रेलवे भूमि के माध्यम से निधियों का जुटाया जाना

1448. श्री महेश्वर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 फरवरी, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रेलवेज रेज टू मैसिव फंड्ज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) रेलवे के पास इस समय राज्य-वार कितने-कितने एकड़ अधिशेष भूमि है तथा कितने एकड़ भूमि क्षेत्र पर विभाग द्वारा वृक्ष उगाये गये हैं एवं इससे प्राप्त लकड़ी को बेचने पर राज्य-वार कितनी-कितनी आय होने की संभावना है ; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं, जहां निजी क्षेत्र द्वारा होटलों का निर्माण किये जाने की योजना है तथा इन होटलों से रेलवे को वर्ष-वार कितनी-कितनी आय प्राप्त होगी ?

रेल मंत्री (श्री सी०के०जाफर शरीफ) : (क) जी हां, बहरहाल, समाचार पत्र में छपी खबर सभी तथ्यों को सही रूप से नहीं दर्शाती है ।

(ख) रेलों के पास फालतू भूमि नहीं है । लगभग 36,000 हेक्टेयर माप की रेलवे भूमि, जिसकी रेलों के भावी विकास कार्यों के लिए आवश्यकता होगी, फिलहाल वृक्षारोपण के लिए उपयोग में लाई गई है। इस संबंध में रेलों द्वारा राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है । जहां तक लकड़ी की बिक्री से होने वाली संभावित आमदनी का संबंध है, एक सर्वेक्षण शुरु किया गया है ।

(ग) रेलवे भूमि पर बजट होटलों की स्थापना का प्रस्ताव अभी वैचारिक स्तर पर है ।